

[ 2009 ] 3 एस. सी. आर. 444

विशाल सिंह

बनाम

राजस्थान राज्य

( आपराधिक अपील सं. 414 सन् 2002 )

25 फरवरी, 2009

[ डॉ. अरिजीत पासायत, वी. एस. सिरपुरकर और अशोक कुमार गांगुली, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302, 341 – अपवाद 4 से धारा 300 – ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और 341 के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया – उच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा – अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: मामले के तथ्यों में धारा 300 के अपवाद 4 का कोई उपयोग नहीं है – अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत सही दोषी ठहराया गया।

शब्दों और वाक्यांशों:

'अनुचित लाभ', 'गैर वाजिब' – का अर्थ

अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और 341 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसलिए अपील.

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: 1. अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी

ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' का अर्थ 'गैर वाजिब' है। [पैरा 7] [449-डी-एफ]

धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य 2003 (5) सुप्रीम 223; प्रकाश चंद बनाम एच.पी. राज्य 2004 (11) एससीसी 381; बायवरपु राजू बनाम ए.पी. राज्य और अन्य। 2007 (11) एससीसी 218 और हवा सिंह और अन्य। वी. हरियाणा राज्य एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 1515/2008 का निपटान 15.1.2009 को किया गया, जिस पर भरोसा किया गया।

2. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी अपीलकर्ता चाकू से लैस था और अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और मृतक और पीडब्लू-6 पर हमला किया। उन्हें चोर करार दिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने उनकी व्यक्तिगत तलाशी शुरू कर दी, जिसका आदेश वर्तमान अपीलकर्ता ने दिया था। जब मृतक ने विरोध किया तो न केवल उसकी पिटाई की गई, बल्कि उसकी छाती पर इतनी जोर से घातक चोट दी गई कि चोट फेफड़े के निचले हिस्से और पेरीकार्डियम तक घुस गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पार्टियों के बीच किसी भी तरह की हाथापाई या अचानक लड़ाई या अचानक झगड़े या तकरार का कोई सबूत नहीं था। यह मृतक और पीडब्लूएस 6 और 7 का अधिकार था कि वे अपनी व्यक्तिगत तलाशी का विरोध करें क्योंकि वे सशस्त्र नहीं थे। ऐसा होने पर, आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के संदर्भ में सही दोषी ठहराया गया है। [पैरा 8] [449-जी-एच; 450-ए-सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 414 सन् 2002

आपराधिक अपील संख्या 596/1997 में राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.8.01 से

महाबीर सिंह, राकेश दहिया, निखिल जैन एंड अजय पाल अपीलकर्ताओं के लिए।

मनीष सिंघवी, आग(राज.) मिलिंद कुमार एंड अरुणेश्वर गुप्ता प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**डॉ० अरिजीत पसायत, जे.** 1. इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ के उस फैसले को दी गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा गया था। आरोपी को चार अन्य लोगों के साथ मुकदमे का सामना करना पड़ा। जहां अभियुक्तगण को आईपीसी की धारा 302 और 341

के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा, वहीं अन्य को धारा 323 और 341 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा।

2. विद्वान विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मामले, जोधपुर ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 341 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। हम अन्य आरोपी व्यक्तियों के संबंध में दोषसिद्धि और सजा से चिंतित नहीं हैं।

3. अभियोजन संस्करण संक्षेप में इस प्रकार है:

रात 8.00 बजे 5.12.1996 को जोधपुर शहर में पी. मुकेश (पीडब्लू-6) अपने चाचा चेतन प्रकाश (पीडब्लू-7) और अपने पिता कालूराम (मृतक) के साथ शादी में फेंके गए बेकार भोजन जो सूअरो के लिये फेका गया था को लाने के लिए साइकिल पर रेलवे स्टेडियम गए थे। रात करीब 10.15 बजे. वे रेलवे स्टेडियम से दो साइकिलों से बेकार भोजन के साथ वापस आ रहे थे। एस.पी.एस. विद्यालय के पास सड़क के किनारे पांच लोग एक स्कूटर और एक हीरो पुच के साथ खड़े थे। उन्होंने मृतक और अन्य लोगों को रोका और पूछा कि वे कहां से आ रहे हैं और उन्हें चोर कहा और उनकी निजी तलाशी लेनी चाही। जब कालूराम और चेतन प्रकाश ने अपनी व्यक्तिगत तलाशी देने से इनकार कर दिया, तो अपीलकर्ता विशाल सिंह ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कालूरानी की छाती पर घातक वार किया। सह अभियुक्त मनोज कुमार ने कालूराम के सिर पर पत्थर से वार किया. बाकी तीन लोगों ने मुक्कों से पिटाई शुरू कर दी. जब पीडब्लू-6 मुकेश और पीडब्लू-7 चेतन प्रकाश ने हस्तक्षेप किया, तो सभी हमलावर भाग निकले।

कुछ कदम चलने के बाद कालूराम बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद घायल कालूराम को टैक्सी के माध्यम से रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां देर रात 1.30 बजे कालूराम की मौत हो गई। अस्पताल में ही मुकेश (पीडब्लू-6) दोपहर 2.15 बजे। गिरिजा शंकर, एस.आई. (पीडब्लू-3) को परचा बयान एक्स.पी.7 दिया, जिन्होंने उसे पुलिस स्टेशन सरदारपुरा भेजा, जहां एफआईआर एक्स.पी./24 सुबह 2.30 बजे दर्ज की गई। इसके तुरंत बाद सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए स्वैच्छिक प्रकटीकरण बयान पर चाकू (अनुच्छेद 1) बरामद किया गया जिसे जब्त कर लिया गया, सील कर दिया गया और एफएसएल को भेजा गया जहां यह मानव रक्त से सना हुआ पाया गया।

जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया. चूंकि आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया, इसलिए मुकदमा चलाया गया।

अपीलकर्ता के साथ मुकदमे का सामना करने वाले मनोज कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अन्य सह-अभियुक्तों को धारा 323 और 341 के तहत दोषी ठहराया गया और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्राथमिक रुख गलत निहितार्थ का था और वैकल्पिक रूप से यह दलील दी गई थी कि एक ही चोट थी और वह भी बिना किसी पूर्व-विचार के अचानक झगड़े और अचानक लड़ाई में थी और इसलिए धारा 302 का कोई मामला नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने याचिका को स्वीकार नहीं किया और जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई।

4. अपील में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनाए गए रुख को दोहराया गया। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ था जैसा कि आरोपी ने दावा किया है। इसलिए, धारा 300 का अपवाद 4 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। हाई कोर्ट ने आरोपी अपीलकर्ता की दलील नहीं मानी और अपील खारिज कर दी।

5. हाई कोर्ट के समक्ष अपनाए गए स्टैंड को दोबारा दोहराया गया। गौरतलब है कि घटना रात करीब 10.15 बजे की है। 5.12.1996 को और तुरंत एफआईआर दर्ज की गई।

6. आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कृत्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, जोश में अचानक हुई लड़ाई में, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और कार्रवाई किए बिना किया गया था। क्रूर या असामान्य तरीके से।

7. आईपीसी की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की वह गर्मी है जो मानव के शांत कारणों को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है; लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है।

वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के बावजूद कि कोई झटका दिया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण उन्हें के संबंध में रखते हैं समान स्तर पर अपराधबोध। 'अचानक लड़ाई' का तात्पर्य आपसी उकसावे और दोनों तरफ से मारपीट से है। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से

एकतरफा उकसावे के कारण नहीं होती है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। लड़ने का कोई पूर्व विचार-विमर्श या संकल्प नहीं है। अचानक झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो इसने इतना गंभीर रूप नहीं लिया होता। इसके बाद आपसी उकसावे और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक सेनानी पर जो दोष लगता है, उसे बांटना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की मदद तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) बिना किसी पूर्वचिन्तन के, (ख) अचानक लड़ाई में हुई हो; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी सामग्रियां मिलनी होंगी। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। जुनून की गर्मी के लिए जरूरी है कि जुनून को ठंडा होने का समय न मिले और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है चाहे वे हथियारों के साथ हों या उनके बिना। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह एक प्रश्न है। तथ्य और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' का अर्थ 'गैर वाजिब' है। इन पहलुओं को धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2003 (5) सुप्रीम 223], प्रकाश चंद बनाम एच.पी. राज्य (2004) में उजागर किया गया है। 11) एससीसी 381), ब्यावरपू राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2007 (11) एससीसी 218) और हवा सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1515/2008 का निपटारा 15.1.2009 को हुआ )।

8. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी अपीलकर्ता चाकू से लैस था और अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और मृतक और पीडब्लू -6 पर हमला किया। उन्हें चोर करार दिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने उनकी तलाश शुरू कर दी, जिसका आदेश वर्तमान अपीलकर्ता ने दिया था। जब मृतक ने विरोध किया तो न केवल उसकी पिटाई की गई, बल्कि

उसकी छाती पर इतनी जोर से घातक चोट दी गई कि चोट फेफड़े के निचले हिस्से और पेरीकार्डियम तक घुस गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पार्टियों के बीच किसी भी तरह की हाथापाई या अचानक लड़ाई या अचानक झगड़े या तकरार का कोई सबूत नहीं था। यह मृतक और पीडब्लूएस 6 और 7 का अधिकार था कि वे अपनी व्यक्तिगत तलाशी का विरोध करें क्योंकि वे सशस्त्र नहीं थे। ऐसा होने पर, आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के संदर्भ में सही दोषी ठहराया गया है। हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

जी०एन०

अपील खारिज।

मंजुला भालोटिया  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोर्ट सं० 13, मुजफ्फरनगर।